

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6407/2023

दिनेश कुमार पुत्र श्री हरि राम, निवासी ग्राम हरदयालपुरा, पिपराली, जिला सीकर-
332027 (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

- उपायुक्त आयकर, (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) कमरा नंबर 413, चौथी मंजिल, जीवन निधि-2, एलआईसी बिल्डिंग, अंबेडकर सर्किल, जयपुर-302005 (राजस्थान)
- आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), दिल्ली-1, तीसरी मंजिल, कमरा नंबर 317, ई-2, ब्लॉक, डॉ. एस.पी. मुखर्जी सिविक सेंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली-110002

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री शफी मोहम्मद चौहान
प्रतिवादी के लिए	:	श्री शांतनु शर्मा के साथ श्री पार्थ वशिष्ठ

माननीय न्यायमूर्ति श्री अवनीश झिंगन

माननीय न्यायमूर्ति श्री उमा शंकर व्यास

आदेश

04/11/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

- यह याचिका आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 148 ए(डी) के तहत पारित दिनांक 07.04.2023 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
- संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने निर्धारण वर्ष 2019-2020 से संबंधित आयकर विवरणी दाखिल की थी। निर्धारण वर्ष 2019-2020 के दौरान अचल संपत्ति की

खरीद के फॉर्म 26 एस/एआईआर में उपलब्ध जानकारी के आधार पर अधिनियम की धारा 148 ए के तहत दिनांक 20.03.2023 को एक नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि संबंधित वर्ष के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोई संपत्ति नहीं खरीदी गई थी, फॉर्म 26 एस/एआईआर में जानकारी गलत थी और याचिकाकर्ता से संबंधित नहीं थी। याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए विभाग द्वारा अचल संपत्ति की खरीद के संबंध में याचिकाकर्ता पर निर्भर सामग्री मांगी गई थी। अधिनियम की धारा 148 ए(डी) के तहत दिनांक 07.04.2023 का आदेश पारित किया गया था जिसमें इसे अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए एक उपयुक्त मामला माना गया था।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किए गए जवाब पर विचार नहीं किया गया, विभाग के पास उपलब्ध दस्तावेज और सामग्री प्रदान नहीं की गई है। चुनौतीप्राप्त आदेश यांत्रिक रूप से पारित किया गया था और पैरा-3 में कहा गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया था, जबकि यह एक स्वीकृत मामला है कि जवाब दाखिल किया गया था।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर नोटिस जारी किया गया था।

5. मुद्दा यह है कि क्या वर्तमान मामले में अधिनियम की धारा 148 ए के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है। दूसरे शब्दों में, निर्धारण अधिकारी ने चुनौतीप्राप्त आदेश पारित करते समय रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री, दाखिल किए गए जवाबों पर विचार किया है और एक स्पष्ट आदेश पारित किया है।

6. वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा, अधिनियम की धारा 147 से 151 को प्रतिस्थापित किया गया था। अधिनियम की धारा 148 ए को अधिनियम की धारा 148 के तहत कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हुए डाला गया था।

7. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (संक्षेप में 'सीबीडीटी') ने **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम आशीष अग्रवाल (उपर्युक्त)** में दिनांक 01/08/2022 के निर्णय के बाद अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।

8. अधिनियम की धारा 148 ए की भाषा और दिशानिर्देशों से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 148 के तहत कार्यवाही शुरू करने से पहले, निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ, निर्धारण अधिकारी, यदि आवश्यक हो, कर-निर्धारण से बचा हुआ दर्शाने वाली जानकारी के संबंध में जांच कर सकता है। करदाता को कम से कम सात दिनों की लेकिन तीस दिनों से अधिक नहीं की तारीख निर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करके सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना है, जिसे आवेदन पर बढ़ाया जा सकता है। पुनर्मूल्यांकन के लिए जिस जानकारी पर भरोसा किया गया है और यदि कोई जांच की गई है तो उसका परिणाम प्रदान किया जाना है। जांच शाखा या अन्य एजेंसी से जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में, रिपोर्ट के प्रासंगिक हिस्से और जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, उनके विवरण के साथ जानकारी का संक्षिप्त सारांश प्रदान किया जाना है। यह निर्णय कि क्या यह धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए एक उपयुक्त मामला है, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर और करदाता द्वारा दाखिल किए गए जवाब पर विचार करते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ लिया जाना है। आदेश उस महीने के अंत से एक महीने के भीतर पारित किया जाना है जब जवाब दाखिल किया गया था और यदि कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया था तो उस महीने के अंत से एक महीने के भीतर जब जवाब दाखिल करने का समय समाप्त हो जाता है।

9. अधिनियम की धारा 148 ए का परंतुक अधिनियम की धारा 148 ए की प्रयोज्यता के अपवाद का प्रावधान करता है।

10. दिशानिर्देशों में, संलग्नक निर्धारण अधिकारी को प्रासंगिक जानकारी की प्रति संलग्न करने के लिए बाध्य करते हैं जिस पर भरोसा किया जा रहा है और यदि कोई सहायक दस्तावेज हैं तो उन्हें भी संलग्न करना होगा।

11. विचाराधीन मामले में धारा 148 ए(डी) के तहत आदेश पारित करते समय, यह दर्ज किया गया था कि याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस (संक्षेप में 'एससीएन') का जवाब दाखिल नहीं किया है, हालांकि यह एक स्वीकृत मामला है कि जवाब दाखिल किया गया था। निष्कर्ष यह निकाला गया कि करदाता ने एससीएन के अनुसरण में अपेक्षित विवरण और सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं और यह अनुमान लगाया

गया था कि याचिकाकर्ता के पास विभाग के पास मौजूद जानकारी के संबंध में कोई विवरण या स्पष्टीकरण नहीं था।

12. इस बात पर विचार नहीं किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा विचाराधीन लेनदेन से इनकार किया गया था और यह दिखाने के लिए फॉर्म 26 एस/एआईआर की प्रति संलग्न की गई थी कि संबंधित निर्धारण वर्ष के दौरान करदाता द्वारा अचल संपत्ति की खरीद का कोई लेनदेन नहीं हुआ था।

13. जवाब पर विचार किए बिना और विभाग के पास उपलब्ध सामग्री प्रदान किए बिना, चुनौतीप्राप्त आदेश पारित किया गया था। अधिनियम की धारा 148 ए और दिनांक 01.08.2022 के दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन में होने के कारण, आदेश को रद्द किया जाता है और मामले को प्रतिवादी नंबर 1 को कानून के अनुसार एससीएन के अनुसरण में आगे बढ़ने के लिए वापस भेजा जाता है।

14. रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(उमा शंकर व्यास), जे

(अवनीश झिंगन), जे

रिया / सचिन / 90

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

